

(i) the persons involved and the police officials found guilty are given exemplary punishment;

(j) victims of atrocities and torture, etc. at the hands of police and other are adequately compensated; and

(k) women organisations and women Members of Legislature are closely associated in making and implementing the laws relating to women."

The motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Mr. Viren Shah, I also clap for you. Mr. Shah, I am thankful to you and to your colleagues, Mr. Bhandariji, Mr. Mathurji, Mr. Chaturvedi and all of you here. ... (Interruptions) . .

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Pranab Mukherjee, please don't run away. away. Mr. Pranab Mukherjee was the one who mediated on behalf of Mrs. Alva. He suggested a solution and I accepted it. So, he also played a key role.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, the same amendments when moved by me were not acceptable to him. But when Mr. Mukherjee moves them, he accepts them.

SHRI VIREN J. SHAH: I did not want to show to the House that I was partial to Mrs. Alva.

SHRIMATI MARGARET ALVA: This shows how much respect he has for a women.

SHRI VIREN J. SHAH: I did not want the House to know how much affection I have for Mrs. Alva and how much influence she has over me. And hence I wanted Pranab to do it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Alva, it is not that he doesn't have respect for women; otherwise he would not have pursued the case of women from the 6th May, 1994. He has asked Mr. Pranab Mukherjee to support it because he wanted to show how good the men are. We are thankful to them. It is a very good thing.

When I was a new Member in this House, I used to observe how Mr. Pranab Mukherjee used to solve most of the problems. I would like him to be in the House most of the time so that if there is any crisis, he can solve it. I hope that there are no crises in future.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, we have wasted some time of the Private Members' Business. I feel that the Private Members' Business should be extended up to 6 o'clock.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is entirely up to the House to decide.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: It can be extended up to 6 o'clock.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. if there is no... (Interruptions) . .

SOME HON. MEMBERS: No. It cannot be extended.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If Members want to sit up to 6 o'clock, it is entirely up to them.

RESOLUTION DEMANDING AMENDMENT OF CONSTITUTION FOR ESTABLISHMENT OF LOKPAL/LOK-AYUKTA TO PREVENT CORRUPTION IN PUBLIC LIFE

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): हमने सब तो कर दिया लेकिन फिर दोहरा देता हूँ। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपकी परनिशान से मैं अपना रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ :

شری محمد مسعود خان : اتر پردیش،
ہم نے مودتو کر دیا لیکن پھر دوسرا درجہ
ہوں۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب : آپ کی پرمیشن
سے میں اپنا رزلولیشن پیش کر رہا ہوں۔

"Having come to the conclusion that all round pervasive corruption in your public life is posing grave danger to the existence and vitality of our institutions, democracy, moral values and freedom, this House urges upon the Government to:—

(1) introduce a Constitution amendment bill in the Parliament to enact a law for the establishment of Lokpal/Lokayukta with the provisions that:

(a) it should cover all the Ministers, representatives of the people and officers of the Government at various levels;

(b) it should confer the authority on Lokpal/Lokayukta to investigate and get the concerned persons prosecuted for committing the crimes of bribery and acts which constitute misuse of power;

(c) Lokpal/Lokayukta may be elected by three fourth majority of the Members of Parliament and the State Legislature respectively and their removal can be effected by a resolutions passed by two third Members of the Parliament and the concerned States Legislature; and

(II) enact an alternative constitutional provision so that on a motion moved by one fourth Members of the Legislature, an investigation could be undertaken against any Minister or high functionary of the Government in respect of acts of bribery, corruption and misuse of power by the Committee of the representatives of the people constituted by Legislatures at Centre and State level."

THE DEPUTY CHAIRMAN: What has been decided? Are we going to adjourn at 5 p.m.?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes, 5 p.m.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right, 5 p.m. (Interruptions).—Mr. Virumbi, please sit down. Now, I would like to ask Mr. Sangh Priya Gautam to come and take the Chair because I was in the midst of a briefing meeting and those people are sitting over there. आइए, गौतम जी। यहाँ बैठिए। आप यहाँ से बहुत अच्छी आवाज में बोलते हैं। अब यहाँ बोलिएगा। आधे घंटे की बात है।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : आज इनकी तरफ से बाद में पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम बार चेयर पर बैठेंगे।

उपसभापति : हाँ, प्रथम बार चेयर पर बैठेंगे। आइए, आइए, बैठिए। आप लोग इनको परेशान मत कीजिएगा।

श्री मोहम्मद सय्यद खान : मैडम ठीक है, लेकिन वह बोलने वाले थे इस पर।

شری محمد مسعود خان : سید صاحب، میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ چیرمین بنیں تو بہت اچھا آواز سے بولیں گے۔

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI-MATI MARGARET ALVA): Now we are assured of a peaceful House.

उपसभाध्यक्ष (श्री संघ प्रिय गौतम) : बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, जो मुझे आपने यह सम्मान दिया। मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अब सदन बड़ी शांति से चलेगा :। . . . (ध्वजध्वनि) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री लंघ प्रिय गौतम) :
श्री मोहम्मद मसूद खान । . . (व्यवधान) . . .

श्री मोहम्मद मसूद खान : मैं आपका आभारी होऊंगा, अगर आप मुझे बोलने दीजिएगा ।

मोहतरम, पिछले 25 साल से यह बात लोक सभा, राज्य सभा में सरकारी और गैर-सरकारी बिल की शक्ल में आती रही है और पता नहीं फिर कैसे उसके बाद रह जाती थी वादा-ए-पर्दा के ऊपर । दुनियां के बहुत से मुमालिक में इस किस्म के बिल एक्ट हो गये हैं, सिर्फ हिन्दुस्तान में इसकी कमी है ।

मोहतरम, मैं आपको तारीख के उन इंसानों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जबकि हिन्दुस्तान में कोई आदमी रिश्वत नाम का कोई चीज नहीं जानता था । यह लार्ड वारेन हेस्टिंग था, जिसने पहली मर्तबा हिन्दुस्तान में रिश्वत को इंट्रोड्यूस किया और तरह-तरह के अंदाज से यह रिश्वत ली, लेकिन इस पहलू पर हम अंग्रेजों की तारीफ करेंगे कि उन्होंने उसके बाद इम्पीचमेंट आफ वारेन हेस्टिंग की भी हिस्ट्री बनाई । वह वारेन हेस्टिंग, जो हिन्दुस्तान में रानी, राजा और ऐसी बड़ी-बड़ी पोस्ट पर बैठकर पैसा लेने का तरीका निकालता था, आखिर में उसको इस कदर इम्पीच किया गया, अगर तारीख मुझको याद है तो उसको जहर खाकर मरना पड़ा । आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर, कितनी सदी गुजरी है उसके बाद भी हिन्दुस्तान के अन्दर बदकिस्मती हमारी यह है कि लॉ पहले यह था और आज भी यह है कि हर आदमी मासूम है, जब तक कि वह गिल्टी साबित न हो । आदाम की नजर भी आज हिन्दुस्तान में यह हो गई है कि हर आदमी करप्ट है, जब तक कि वह साबित न कर दे कि हम करप्ट नहीं हैं । इस चीज को घुमाने के वास्ते बहुत जरूरी है कि लोकपाल और लोकायुक्त का गिल आये ।

मैं चन्द महीने पहले अपने गांव गया था । एक किसान ने मुझसे कहा कि साहब, यह समझ में नहीं आता कि रिश्वत ऊपर

से चल रही है कि नीचे से चल रही है । बड़े लीडर कहते हैं कि ऊपर से चल रही है । उसने अपना एक किस्सा बताया कि मुझको एक काम के वास्ते लेखापाल के यहाँ जाना पड़ा । उसने कहा कि इस काम के लिये मैं इतना रुपया लूंगा, तब दूंगा । मैंने बड़ी सिफारिश की कि रुपया बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं मजबूर हूँ, सब खुद ही नहीं खाऊंगा, मुझको अपने बड़े अफसर को भी देना है । उसने कहा कि मैं उसके बड़े अफसर के यहाँ भी गया तो उसने कहा कि मैं ही सब नहीं खाऊंगा जो मिलेगा, मुझको अपने बड़े अफसर को भी देना पड़ेगा । इस तरह वह कहता रहा कि जहाँ तक मेरी सकत थी मैं गया, ऊपर से आप लोग देखिये । तो आज पोजीशन यह है कि बड़े धड़ल्ले से, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का आदमी जब रिश्वत लेता है तो यह कहता है कि साहब सारा मुझको नहीं खाना है बल्कि इसमें बहुत से लोगों को, बहुत सी स्टेज पर मुझको देना है ।

माहोल बदलता है वक्त के साथ, अगर कानून उसके साथ न बदले तो जाहिर बात है कि बुनियाद बड़ी तेज हो जाती है । मैं सन 56 में वकालत में आया । प्लेंट मैंने लिखा तो एक पुराना मुक्किल आया और उसने दस्तखत किया अपने नाम के आगे "बकलमखुद" । मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह "बकलमखुद" क्या है । मैंने उससे पूछा कि भाई "बकलमखुद" क्यों लिख रहे हो, उसने कहा कि बस मेरी आदत है इसलिये "बकलमखुद" लिख रहा हूँ । दूसरा आया, उसने भी लिखा । तीसरा आया, उसने भी लिखा । मुझको सख्त ताज्जुब हुआ, बड़े-बड़े विद्वानों से मैंने पूछा कि यह "बकलमखुद" का क्या मतलब है ? यानी लिटरेरी तर्जुमा तो मुझे मालूम है, लेकिन यह "बकलमखुद" कस्टम में कैसे आया ? कोई इल्मीनानवकश जवाब मुझे नहीं दे सका । सन 1872 का एक कागज जब मैंने देखा और बाजीबुल अर्ज जब मैंने पड़ा, तब जाकर यह चीज क्लियर हुई कि 19वीं सदी में अगर किसी वगैर पढ़े-लिखे आदमी को किसी दस्तावेज पर दस्तखत करना होता था तो वह किसी पढ़े-लिखे आदमी से जुधानी कह देता था कि मेरी तरफ से तुम दस्तखत कर दो । वह पढ़ा-लिखा आदमी दस्तखत करता था ।

उसका नाम लिखकर और "बकलम अपने" यह लिखता था और अगर पढ़ा-लिखा शख्स दस्तावेज पर अपने दस्तखत करता था, तब लिखता था "बकलमखुद"। वह चीज रायज थी 20 वीं सदी में भी। लेकिन उस बक्त में जबानी हिदायत पर दूसरा पढ़ा-लिखा आदमी दस्तखत कर देता था और कहीं उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कह सके कि मैंने इसको हिदायत नहीं दी। आज का दौर वह है कि दस्तावेज पर खुद आदमी लिखता है, दो गवाह रहते हैं, रजिस्ट्री आफिस में जाकर रजिस्ट्री होती है, तब भी 25 परसेंट केस कोर्ट में यह आते हैं कि मेरे दस्तखत नहीं है। आज माहौल यह है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि माहौल के साथ अगर कानून नहीं आयेगा तो जाहिर बात है कि जो भी गलत रिवाज होगा वह इतना बड़ा मर्ज हो जायेगा जिस मर्ज को कभी खत्म नहीं किया जा सकता।

उपभाष्यक (श्री सुरेश पचोरी)
पीठासीन हुए।

मान्यवर, खाली पैसे की रिश्वत ही रिश्वत नहीं होती, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अगर किसी ने कोई काम कर दिया तो यह भी एक किस्म की रिश्वत होती है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। रात मेरे पास टेलीफोन आया कि साहब, यहाँ पंचायत का इलेक्शन हो रहा है पंचायत के इलेक्शन में गांव सभा का नंद-परिद देगे से शुरू करके और आखिर तक यानी कि बी०डी०सी० के मेंबर का क्षेत्र बनाना, ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र बनाना, जिला परिषद के मेंबर का क्षेत्र बनाना, यह सब आजमगढ़ में इस तरह से किया गया है और आज सुबह मैंने "कौमी आवाज" खबबार में पढ़ा कि सारे उत्तर प्रदेश में इस तरह से किया गया है कि गलत तादाद लोगों की रखकर, आजमगढ़ में तो कोई मुस्लिम गांव ऐसा रह ही नहीं गया जहाँ कि मुस्लिम इलेक्शन लड़े। उसे या तो रिजर्व में या हरिजन में कर दिया गया है। तो मेरे पास टेलीफोन आया तो मैंने कहा कि जो मसीहा बने हैं, उनसे कहो भई। यह भी एक किस्म की नस्लकृशी, किसी नस्ल को या फिरके को बरबाद करने की कोशिश है। ऐसा भी कोई

सरकार अगर करती है, ऐसा भी अगर कोई अफसर करता है चाहे वह आजमगढ़ का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, वह भी इस परव्यू में आना चाहिये। किसी फिरके को सियासी तौर से वंचित कर देना, ऐसी साजिश करना, यह भी एक करप्शन है।

मोहतरम, इस पर फोरन रोक इस वजह से करानी चाहिये कि मुझको मिस्त्र की एक तारीख याद आती है कि मिस्त्र में जहाँ रिश्वत थी, वहाँ इसे नजराना बोला जाता था, नजराना लिया जाता था। (व्यवधान)

वहाँ के लोगों ने कानून बनाया कि नजराना लेना खिलाफ कानून है। तो उन लोगों ने एक तरकीब इजाद कर दी। आज जेसे जुम्मा है, तो जिसको रिश्वत या नजराना लेना होता है तो वह कहता था कि आज जुम्मा है। जिसको देना था तो कहता था कि आज बृहस्पत है और इस प्रकार एक लाख रुपये की बाजी लग जाती थी। उसके बाद कलेंडर देखा जाता था और अगर जुम्मा निकलता था तो लिहाजा एक लाख रुपया उसको दे देना पड़ता था। तो हमको बहुत होशियारी से कानून भी बनाना है कि कहीं नजराना लाटरी में न निकल आये और उसके बाद बात जहाँ से रहे वहीं पहुँचे।

तो मान्यवर मैं ज्यादा टाईम न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह अहद कितना कंफ्रेंसिव होना चाहिये, मेरा यह रिजोल्यूशन है और सरकार की तरफ से आना चाहिये। जैसे कोई बीमार आदमी दवा लेने के बाद मेडिकल चैकअप कराता है साल में एक मर्तबा, दो मर्तबा। तो यह प्रोविजन होना चाहिये, हर बड़ा आफिसर लोक आयुक्त के सामने जाकर अपना मेडिकल चैकअप कराकर सर्टिफिकेट ले कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं या कैसे हैं, तभी वह पॉस्ट

र रहे । अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा है: "रूलाता है तेरा नजारा ए हिन्दुस्तान मुझको, कि इबरात खेज है तेरा फसाना सब फसानों में । न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिन्दो-स्तां वालो, तुम्हारी दास्तान तक भी [न होगी दास्तानों में । उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, अन्दलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली, तज फुसा मेरी । उठाये कुछ वरक लाले ने, कुछ नर्गिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी ।"

मौतरम, हमारी दास्तान जो बिखरी हुई है उसको समेटना है । जो एक फॉरेनर लार्ड वारेन हैस्टिंग यहां आया था और जिसने यहां इजाद किया था, उस इजाद को खत्म करना है । इस मुल्क को साथ-सुथरा नजाम देना है । अगर यह साफ-सुथरा नजाम और करप्ट लोगों को कहीं अकुश लगाने के लोक आयुक्त की तरह से अगर कोई इंस्टीट्यूशन होगा, तो आज जो हमको सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है, क्यों कि यहां की सरकार की बदौलत जो एक करोड़ रुपया मिलता है जिले के अन्दर काम कराने के वास्ते । तो पता नहीं उसमे 40 फीसदी भी काम होता है या 50 फीसदी काम होता है । इस प्रकार किस तरह से वह रिश्वत और करप्शन का नजर हो जाता है । तो इन सब चीजों को सामने रखकर के और इस माहौल को सामने रख कर के इस हाउस से अपील करंगा कि मेरे रिजोल्यूशन की ताईद करें ।

श्री محمد مسعود خان अत्री प्रधान :

मैं आपका अजारी होंगा । اگر آپ مجھے بولتے
دیکھئے گا ۔ محترم ۔ پچھلے ۲۵ سال سے یہ بات
لوک سبھا ۔ راجیہ سبھا میں سرکاری اور غیر سرکاری

بل کی شکل میں آتی رہی ہے اور یہ نہیں
پھر کیسے اس کے بعد رہ جاتی تھی وعدہ
پردہ کے اوپر دنیا کے بہت سے ممالک
میں اس قسم کے بل اور ایکٹ ہو گئے ہیں
صرف ہندوستان میں اس کی کمی ہے ۔

محرم میں آپکو تاریخ کے ان سالوں
کی طرف سے جانا چاہتا ہوں جبکہ ہندوستان
میں کوئی آدمی رشوت نام کی کوئی چیز نہیں
جانتا تھا ۔ یہ "لارڈ وارن ہاسٹنگ" تھا جس
نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں رشوت کو
انٹروڈیوس کیا اور طرح طرح کے انداز
سے یہ رشوت لی لیکن اس پہلو پر ہم انگریزوں
کی تعریف کریں گے کہ انہوں نے اس کے
بعد امپچیٹ آف وارن ہاسٹنگس کی بھی
ہسٹری بنائی ۔ وہ وارن ہاسٹنگ جو ہندوستان
میں رانی راجہ اور ایسی بڑی بڑی پوسٹ
پر بیٹھا کہ پیسہ لینے کا طریقہ نکالتا تھا ۔

آخر میں اس کو اسقدر امپیج کیا گیا ۔ اگر
تاریخ بچھ کو یاد ہے تو اس کو زیر کھا کر
مڑنا پڑا ۔ آج بھی ہندوستان کے اندر کتنی
صدی گزری ہے اس کے بعد بھی ہندوستان
کے اندر باقی قسمتی ہماری یہ ہے کہ لار پہلے
یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ ہر آدمی معصوم
ہے جب تک کہ وہ گلٹی ثابت نہ ہو عوام
کی نظر بھی آج ہندوستان میں یہ ہو گئی ہے

کہ ہر آدمی کرپٹ ہے۔ جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں۔ اس چیز کو گھمانے کے واسطے بہت ضروری ہے کہ لوگ پال اور لوک آئیکتہ کابل آئے۔ میں چند مہینے اپنے گاؤں گیا تھا۔ ایک کسان نے مجھے کہا کہ صاحب یہ سمجھ نہیں آتا کہ رشوت اوپر سے چل رہی ہے کہ نیچے سے چل رہی ہے۔ بڑے لیڈر کہتے ہیں کہ اوپر سے چل رہی ہے اس لئے اپنا ایک قصبہ بنایا کہ مجھ کو ایک کام کے واسطے لیکھ پال کے یہاں جانا پڑا۔ اس نے کہا کہ اس کام کے لئے میں اتنا روپیہ لوں گا۔ تب دوں گا۔ میں نے بڑی سفارش کی کہ روپیہ بہت زیادہ سے رہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں مجبور ہوں۔ سب خود ہی نہیں کھاؤنگا۔ مجھ کو اپنے بڑے افسر کو بھی دینا ہے۔ اس نے کہا تو میں اس کے بڑے افسر کے یہاں بھی گیا تو اس نے کہا کہ میں ہی سب نہیں کھاؤنگا۔ جو ملے گا مجھ کو اپنے بڑے افسر کو بھی دینا پڑے گا۔ اس طرح وہ کہتا رہا اور جہاں تک میری سکت تھی میں گیا۔ اوپر سے آپ لوگ دیکھئے تو آج پوزیشن یہ ہے کہ بڑے دھڑے سے جا ہے نیچے کاچا ہے اوپر کا آدمی جب رشوت لیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ صاحب سارا مجھ کو نہیں کھانا ہے بلکہ

اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سی اسٹیج پر مجھے دینا ہے۔ ماحول بدلتا ہے وقت کے ساتھ۔ اگر قانون ان کے ساتھ نہ بدے تو ظاہر بات کہ بنیاد بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ میں سڑکوں میں وکالت میں آیا۔ پلینٹ میں نے کھا تو ایک پرانا موٹر گلا آیا اور اس نے دستخط کیا اپنے نام کے آگے ”بقلم خود“۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ”بقلم خود“ کیلئے ہے۔ میرے اس سے پوچھا کہ بھائی ”بقلم خود“ کیوں لکھ رہے ہو اس نے کہا کہ بس میری عادت ہے۔ اس لئے ”بقلم خود“ لکھ رہا ہوں۔ دوسرا آیا اس نے بھی لکھا۔ تیسرا آیا اس نے بھی لکھا۔ مجھ کو سخت تعجب ہوا۔ بڑے بڑے دو دنوں سے پوچھا کہ یہ ”بقلم خود“ کا کیا مطلب ہے یعنی ٹھیک ترجمہ تو مجھے معلوم ہے۔ لیکن یہ ”بقلم خود“ کسٹم میں کیسے آیا۔ کوئی اطمینان بخش جواب مجھے نہیں دے سکا۔ سنہ ۸۷۲ کا ایک کاغذ جب میں نے دیکھا اور واجب العزمیٰ جب میں نے پڑھا تب جا کر یہ چیز کھیر ہوئی کہ ۱۹ ویں صدی میں اگر کسی بغیر پڑھے لکھے آدمی کو کسی دستاویز پر دستخط کرتا ہوتا تھا تو وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے زبانی کہہ دیتا تھا کہ میری طرف سے تم دستخط کر دو۔ وہ پڑھا لکھا آدمی دستخط کر دیتا تھا۔

اس کا نام لکھ کر اور "بقلم اپنے" یہ لکھنا تھا اور اگر پڑھا لکھا شخص دستاویز پر اپنے دستخط کرتا تھا۔ تب لکھتا تھا "بقلم خود" یہ چیز رائج تھی۔ ۱۷ویں صدی میں بھی لیکن اس وقت میں زبانی ہدایت پر دوسرا پڑھا لکھا آدمی دستخط کر دیتا تھا اور کہیں اس کی تمہت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ آج کا دور وہ ہے کہ دستاویز پر خود آدمی لکھتا ہے۔ دو گواہ رہتے ہیں۔ رجسٹری آفس میں جا کر رجسٹری ہوتی ہے۔ تب بھی ۲۵ پرنٹ کیس کو رٹ میں یہ جاتے ہیں کہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ آج ماحول یہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماحول کے ساتھ اگر قانون نہیں آئے گا تو طاہر بات ہے کی جڑ بھی غلط رواج ہوگا وہ اتنا بڑا مرض اور جلے گا جس

ایک جھانڈیکش "شرعی سریش بچوری" بیٹھا سین مرنے کو کبھی جہم نہیں کیا جاسکتا۔

مانیہدر۔ خالی پیسہ کی رشوت ہی رشوت نہیں ہوتی۔ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو یہ بھی ایک قسم کی رشوت ہوتی ہے۔ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ رات میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ صاحب یہاں پنچایت کا ایکشن ہو رہا ہے اور

پنچایت کے ایکشن میں گاؤں سبھا کی نند پرند دینے سے شروع کر کے اور آخر تک یعنی کہ بی۔ ڈی۔ سی کے ممبر کا کشیتہ بنانا۔ بالکاپٹھ کا کشیتہ بنانا۔ ضلع پریش کے ممبر کا کشیتہ بنانا یہ سب اعظم گڑھ میں اس طرح سے کیا گیا ہے اور آج صبح میں نے "قومی آواز" اخبار میں پڑھا کہ سارے اتر پردیش میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ غلط تعداد لوگوں کی لکھ کر اعظم گڑھ میں تو کوئی مسلم گاؤں ایسا رہا ہی نہیں گیا جہاں کہ مسلم ایکشن لڑے۔ اسے یا تو ریزرو میں یا ہریجن میں کر دیا گیا ہے تو میرے پاس ٹیلی فون آیا تو میں نے کہا کہ جو مسیح جانے ہیں ان سے کہو بھائی۔ یہ بھی ایک قسم کی نسل کشی کبھی نسل کو یا فرقہ کو برباد کرنے کی سازش ہے ایسا بھی کوئی سرکار اگر کرتی ہے۔ ایسا بھی کوئی افسر اگر کرتا ہے چاہے وہ اعظم گڑھ کا ہو چلے کہ کسی اسٹیٹ کا ہو وہ بھی اس پر یو میں آنا چلے بیٹے کسی فرقہ کو سیاسی طور سے ونجیت کر دینا۔ ایسی سازش کو ناوہ بھی ایک کرپشن ہے محترم۔ اس پر فوراً روک اس وجہ سے کراپی چاہیے کہ مجھ کو مصر کی ایک تاریخ یاد آرہی ہے کہ مصر میں جہاں رشوت تھی وہ اسے نذرانہ بولا جاتا تھا۔ نذرانہ لیا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے قانون بنایا کہ نذرانہ لینا اخلاف قانون ہے تو ان لوگوں نے ایک

تہ کیسب ایسا کر دیں۔ آج جیسے جمعہ ہے تو جس کو رشوت یا نذرانہ لینا ہوتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ آج جمعہ ہے جس کو دینا تھا تو کہتا تھا کہ آج برہمنیت ہے اور اس پر کار ایک لاکھ روپیہ کی بازی لگ جاتی تھی اس کے بعد کلنٹر دیکھا جاتا تھا اور اگر جمعہ نکلتا تھا تو لہذا ایک لاکھ روپیہ اس کو دے دینا پڑتا تھا تو ہم کو بہت ہوشیاری سے قانون بھی بنانا ہے کہ گھیس نذرانہ لائری میں نہ نکل آئے اور اس کے بعد بات جہاں سے رہے وہیں پہنچے۔

تو مانیہ ور میں زیادہ ٹاکم نہ لے کر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عہد کہتا کمپری ہینسو ہونا چاہیے میرا یہ ریزولوشن ہے اور سرکار کی طرف سے آنا چاہیے جیسے کوئی بیمار آدمی دوا لینے کے بعد میڈیکل چیک اپ کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تو یہ پرووین ہونا چاہیے۔ ہر بڑا آفیسر لوک آیکٹ کے سامنے جا کر اپنا میڈیکل چیک اپ کر کر سٹیفکیٹ لے کہ ہم ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں یا کیسے ہیں۔ یہی وہ پوسٹ پر ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ۔
رولاتا ہے تیرا نظارہ لے ہندوستان مجھ کو
کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسے ہندوستان والو
تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
آزادی قمریوں نے، ملطیوں نے، غنڈہ پیوں نے
چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزِ فغاں میری
اٹھائے کچھ ورقِ لالہ نے، کچھ زگس نے، کچھ گل نے
سچ میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔
محترم ہماری داستان جو بکھری ہوئی ہے
اس کو بیٹنا ہے جو ایک فارنر لارڈ ولن ہسٹنگس
یہاں آیا تھا اور جس نے یہاں ایجاد کیا تھا اس
ایجاد کو ختم کرنا ہے اس ملک کو صاف ستھرا
نظام دینا ہے۔ اگر یہ صاف ستھرا نظام اور کریٹ
لوگوں کو انکسٹنکشن کے لئے لوک آیکٹ کی
طرح سے اگر کوئی انسٹی ٹیوشن ہوگا تو آج جو
ہم کو سب سے زیادہ بولنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ
یہاں کی سرکار کی بدولت جو ایک کروڑ روپیہ
ملتا ہے ضلع کے اندر کام کرانے کے واسطے
تو پتہ نہیں اس میں ۵ فیصدی بھی کام ہوتا ہے
یا ۵ فیصدی کام ہوتا ہے۔ اس پر کار کس طرح سے
وہ رشوت اور کرپشن کی نذر ہو جاتا ہے۔ تو
ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اور اس
ماحول کو سامنے رکھ کر کہ اس ہاؤس سے
اچیل کر دیں گا کہ میرے ریزولوشن کی تائید کریں
"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is one amendment by Shri Chimanbhai Mehta. The amendment may be moved without any speech.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, I move:

That at the beginning of para 5 of the Resolution, the following be added,

"Lokpal may be nominated by the entire Supreme Court Judiciary and Lokayukta by the entire High Court Judiciary in transparent manner or"

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now the Resolution and the Amendment are open for discussion. Shri T. N. Chaturvedi.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Sir, I am of the considered view that today this House has before it a matter of vital importance, a Resolution which really is of great significance for the future of this country and its democracy. Sir, I have also moved a Resolution of the same kind. Since the Resolution, that my friend, Shri Mohd. Masud Khan, has moved, reflects, by and large, what is embodied in my Resolution, I thought that I should whole-heartedly support it. There are a large number of nuances, aspects, and complexities of this problem that this House may like to go into. Sir, since the Second World War the nature of public administration as well as of the Government has specially undergone considerable changes. The State has become much more complex and has also assumed a large number of functions. The question of assumption of a large number of functions is again in dispute today or there is a question

mark on this particular issue. This is something like a pendulum, whether there should be greater intervention by the State or less intervention by the State. If it is less intervention, what is the specified role, nature, character of that intervention? These are the days of liberalisation. But it is still said that so far as the State is concerned, it may not be an interventionist State but it will continue to be a facilitator. It will facilitate the economic development, growth, social progress of the country, and will maintain harmony. It is not only that, Sir, but also the expectations of the people have been greatly heightened. Long back it was said that this was the century of the common man, an era of rising expectations. This has been the challenge before the new democratic nations.

So far as the aspect of corruption is concerned, there had been a large number of cases of history. My friend, Shri Masud Khan has mentioned some of them and I will also have an occasion to mention some. But at this moment, I would like to say that this question of setting up of the Lokpal and its counterpart, the Lokayukta, or what is, in common parlance or elsewhere, known as the Ombudsman, has primarily two aspects. One is regarding corruption and the need to ensure purity in public life, to restore integrity in public office and in Government functionaries. This is one aspect. The other aspect of it is maladministration. The question is redressal of citizens' grievances, the accessibility to the citizen, who can somehow be ensured that his rights are protected. This situation becomes much more accentuated when the democratic expectations are raised. Let us take the Preamble of the Constitution, the Directive Principles of State Policy of the Constitution or the fundamental rights, all of them enshrine the hopes and aspirations of the freedom movement. Some kind of a cultural ethos, some kind of a direc-

tion, a direction which is multi-sided, which is rooted in the problems of the day and which ensures a better tomorrow for the people of this country, all these are embodied and enshrined in the Constitution by the founding fathers. There are repeated elections in our country. It is a great tribute to the vitality, the vibrancy of the democratic process in our country that despite some aberrations here and there, by and large, our country has maintained the democratic traditions, the democratic processes on an even keel. In such a vast country with all kinds of diversities we have held many general elections democratically all over the country and in the States separately. They earned encomiums all over the world. We may have some dissatisfaction legitimately at some point of time here and there. But, by and large, that is the situation. Sir, to stabilise this democratic process, these democratic foundations we, today, need to reinforce the Constitutional mechanism that exists so far. Mr. Vice-Chairman, Sir, we find that the rights that we want our people to have, acquire and enjoy are embodied in the Constitution. But, there is still in our country and elsewhere, for a number of reasons, the so-called emphasis on Human Rights. For us the question is not of providing some new Human Rights. But for us the problem is that this Human Rights that were assured to the people of this country how they, really, fructify how they acquire greater significance and how they really become available to the people. As you know, Sir, we have in this country because of this a number of Committees and Commissions. These are the National Commission for Women, the Human Rights Commission, which is the latest one, and the Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and so on. They, in a fragmented manner, also attend to this problem of Human Rights. The need really is that this entire question is

looked at from a holistic point of view to avoid the kind of duplication and the kind of splitting responsibility that is there now. I am mentioning this particularly in the context of the report of the Estimates Committee. Sir, the Estimates Committee of the Lok Sabha in its first report on the System of Redressal of Grievances pointed out:—

“The existing arrangements in the Ministries for the redressal of public grievances were ineffective. There was a lack of synergy between the efforts of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances and those of various other Ministries and Departments towards the redressal of public grievances.”

Sir, I am not making this point or quoting it with a view to criticising any Department. My only intention, my limited intention, is to point out or bring to the notice of this House the question of coordinated efforts so far as the redressal of grievances is concerned. When the grievances are not redressed, the people opt for all kinds of ways and means. It gives rise to touts, it gives rise to brokers and all kinds of middlemen to flourish. It is of paramount importance in a situation of liberalisation because the period of liberalisation, if I may put it, is something like a twilight period—one time ends and another is yet to begin. That is the time and it is at this kind of a time, as you find in the twilight period, the denizens of the neither world appear. All those insects which cannot see the light of day, somehow or other, make their appearance and they exploit and take advantage of that situation of change, of flux and of transition. That is why it becomes very important that during the period of change, flux and transition, we remain more cautious and see that our constitutional machinery is so empowered that it can contain such elements. Sir, the biggest testimony to this has been what is known as the JPC. As a Member of the JPC, I am aware of it and all Members of this august House are well aware

[Shri Triloki Nath Chaturvedi]

of the position. There is another reason why this is very necessary. There are two aspects to it. One is the question of ensuring accountability—accountability of the administration. You can say, accountability of the State also. Sir, the State functions through the Government, a unit which is visible to the people. The Government functions through its widespread administrative mechanism and machinery. That machinery and mechanism comes into day-to-day contact with the people through the reports of the Public Accounts Committee, or the reports of the Estimates Committee or other evaluation committees. We discuss the Ministers' Budgets and appropriation accounts. On many occasions, Members have risen to complain that somehow or the other, there is no accountability so far as the programmes are concerned, so far as the results are concerned or so far as even the propriety involved is concerned. That primarily relates to administration—the administrative mechanism. Sir, to this House, the Government is responsible. It is for the Government to ensure that the machinery which functions under it, works and functions in such a way that accountability can be established. The other is regarding the question of responsibility. Responsibility also has many facets to it. One is that political responsibility of the Government to the Parliament. Sir, it is not a question of a "No Confidence Motion" and so on. The Government is responsible to the House, to the Parliament, because we represent the people of India. That is the assumption, that is the idea and that is the aspiration. If that is so, then all those facets of responsibilities have also to be taken into account. If I may broadly say, it is a political responsibility. It is also a question of financial accountability and it is also a question of policy accountability. That is why, long back, Government initiated a move towards having a performance budget. The idea was to permeate the

entire process with this sense of accountability and responsibility. Not only that, Sir, I may be allowed to dilate. When people say that there should be a sense of responsibility, the sense of responsibility has a psychological dimension. Do we really feel ourselves responsible for something? We feel responsible to whom and for what and then what are those instruments?

What are those tools through which that responsibility can be ensured? This question of accountability and responsibility relates to administrative responsibility and political responsibility... (*Interruptions*)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is 5 o'clock now and I think Mr. Chaturvedi can continue his speech on the next Private Members' Business day. I request you to adjourn the House now... (*Interruptions*)

श्री जगदीश प्रताप भार्गव : उपसभाध्यक्ष महोदय, 6 बजे तक हाउस बैठता है। स्पेशल मेशन खत्म दीजिए।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, we have to make our Special Mentions... (*Interruptions*)

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, Special Mentions can be taken up on Monday... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, let me make my Special Mention. I will not take more than two minutes. And I believe the other Members are not present.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, you adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I adjourn the House till Monday.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 27th March, 1995.